भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3701

उत्तर देने की तारीख 25/03/2026

स्ट्राइड योजना की प्रगति

3701# **श्री मोकरिया रामभाई:**

श्री दीपक प्रकाश:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर-विषयक अनुसंधान योजना (स्ट्राइड) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या घटक-1 के अंतर्गत चयनित संस्थानों के लिए प्रारंभिक तीन वर्षीय चक्र पूरा हो चुका है और क्या मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो अनुसंधान क्षमता संवर्धन, नवाचार और सहयोगात्मक अनुसंधान परिणामों के संदर्भ में प्रमुख निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतर-विषयक अनुसंधान को और अधिक मजबूत करने के लिए स्ट्राइड योजना के अंतर्गत कोई विस्तार, पुनर्गठन या अतिरिक्त घटक शामिल किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ)**:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसंधान संस्कृति, नवाचार को सुदृढ़ करने और अंतर-विषयक अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था हेतु अंतर-विषयक अनुसंधान योजना (स्ट्राइड) शुरू की। इसके निम्नलिखित तीन घटक थे:

1. घटक-1: अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है।
2. घटक-2: राष्ट्रीय विकास के लिए अंतर-विषयक अनुसंधान और समावेशी नवाचार।

3. घटक-3: मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव वाला अंतर-विषयक अनुसंधान।

यूजीसी ने सूचित किया है कि योजना के तहत प्रस्ताव वर्ष 2019 के दौरान आमंत्रित किए गए थे और प्रस्तावों की गहन समीक्षा के बाद, स्ट्राइड के तहत घटक-1 के लिए अंततः 35 संस्थाओं का चयन किया गया था। घटक-1 के तहत चयनित सभी संस्थाओं के लिए 3 वर्षीय चक्र पूरा हो गया है और 27 एचईआई ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

वर्तमान में, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर-विषयक अनुसंधान (स्ट्राइड) योजना परिचालन में नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), फरवरी, 2024 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, 2023 के माध्यम से स्थापित किया गया था। एएनआरएफ जुलाई, 2025 में शुरू किए गए अपने कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के माध्यम से मूल विज्ञान की गहराई को सामाजिक विज्ञान और मानविकी की संदर्भात्मक अंतर्दृष्टि के साथ लाने वाले बहु विषयक अनुसंधान को सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समकालीन सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है जिसके लिए एकीकृत, अंतर-विषयक समाधानों की आवश्यकता है। कार्यक्रम का कुल परिव्यय 5 वर्षों के लिए 375 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने सामाजिक और मानव विज्ञान में अनुसंधान हेतु शीर्ष निकाय के रूप में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की भी स्थापना की है। आईसीएसएसआर अपनी विभिन्न अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से अंतर-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है, सहायता प्रदान करता है और वित्त पोषित करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, आईसीएसएसआर ने 3,55.94 करोड़ रुपये के संस्वीकृत बजट के साथ 6468 लाभार्थियों को 2156 अंतर-विषयक अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की हैं।

वर्ष 2023-24 में, आईसीसीएसआर के तहत अंतर-विषयक अनुसंधान हेतु वित्त पोषण 47,95,20,174 रुपये था। यह वर्ष 2024-25 में बढ़कर 159,35,31,900 रुपये (+232.32%) और वर्ष 2025-26 में 148,63,36,600 रुपये (+209.96%) हो गया। कुल मिलाकर, यह वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की तीन वर्ष की अवधि में आईसीएसएसआर द्वारा अंतर-विषयक अनुसंधान वित्तपोषण में 200% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

*****